रोप-वे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों के विकास में केन्द्र सहयोग करेगा : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से की मुलाकात

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हे राजस्थान में राजमार्गों के विकास के लिए उनके द्वारा दिये गये निरन्तर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। पिछले दस साल में केन्द्र सरकार ने राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग एक लाख करोड़ के कार्यों को स्वीकृत किया है।

दिया कुमारी ने उन्हे आश्वस्त किया कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने राजस्थान को सेन्ट्रल रोड तथा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड-सीआरआईएफ से ज्यादा सड़कें स्वीकृत करने की भी मांग की।

राजस्थान से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यो का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माँग की कि बृज-चौरासी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर विकसित किया जाये। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार की 'पर्वतमाला योजना' के अन्तर्गत राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक और पर्यटन महत्व के स्थानों पर रोपवे के निर्माण की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा जारी करने की मांग की।

उन्होंने राज्य में बनने वाले 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की स्वीकृति भी केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी किये जाने का अनुरोध किया। दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में बनने वाले नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे में से जयपुर-किशनगढ़-जोधपुर प्रोजेक्ट की डीपीआर एनएचएआई को भिजवा दी गयी है तथा बाक़ी आठ एक्सप्रेस-वे का कार्य की स्वीकृति के लिए भी केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। गडकरी ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को कहा कि राजस्थान में राजमार्ग के विकास के लिए 8322 करोड़ रुपये का प्लान है तथा जरुरत पड़ने पर अतिरिक्त कार्यों की भी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उन्होने दिल्ली-जयपुर-किशनगढ़ मार्ग पर कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए भी ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।

दिया कुमारी ने गडकरी से मुलाकात के दौरान बड़ौदामेव-कुम्हेर-नदबई-भरतपुर हाईवे, मथुरा से नदबई होते हुए जयपुर-आगरा रोड से जोड़ने के लिए लिंक हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे से बांदीकुई में प्रवेश तथा निकास के लिए कनेक्टिविटी सर्वे, जयपुर-किशनगढ़ परियोजना तथा जयपुर-रींगस मार्ग पर ब्लैक स्पॉट सर्वे, जयपुर, उदयपुर तथा अजमेर में रिंग रोड़ के निर्माण, जोधपुर में फ़ोर-लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को शीघ्र पूरा करने तथा भरतपुर के सारस चौराहे, घना, सेवर मोड और शीशम तिराहे पर फ्लाईओवर निर्माण तथा मेडिकल कॉलेज, टेक्नोलॉजी पार्क तथा बरसो के पास अंडरपास और सर्विस रोड आदि मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की।

दिया कुमारी ने भरोसा जताया कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने राजस्थान में हाईवे निर्माण के लिए पिछले दस सालों में भरपूर मदद की है, उसी प्रकार राजस्थान की डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में भी आधारभूत ढाँचे के विकास के नये आयाम स्थापित होंगें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में भेंट की।

हाईकोर्ट में जज ने मौके पर ही मशीन मंगाकर नपवाई ऊंचाई

केंद्र सरकार की सशस्त्र बल भर्ती-2023 में अभ्यर्थी हाइट कम नापने को कोर्ट में चुनौती दी थी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार की सशस्त्र बल भर्ती- 2023 में अभ्यर्थी की हाइट कम मापने के मामले में मौके पर ही संबंधित मशीन मंगाकर हाईकोर्ट के डॉक्टर से हाइट नपवा ली। हालांकि हाइट समान ही आने पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मंजीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में पैरामिलिट्री फोर्स के हाइट मापने के उपकरण को लाया गया। इस दौरान विभाग के असिस्टेंट कमांडेंट अनुपम सिंह, डिप्टी कमांडेंट यशवीर और डॉ. टीआर चौधरी पेश हुए। इस दौरान अदालत ने हाईकोर्ट स्थित चिकित्सालय में तैनात डॉ. अजय पुरोहित को बुलाकर याचिकाकर्ता की हाइट नापने को कहा। डॉक्टर की ओर से याचिकाकर्ता की हाइट 168.5 सेंटीमीटर होना बताया। इस पर अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसकी हाइट में कोई अंतर नहीं आया है। दरअसल केन्द्र सरकार ने सशस्त्र बल के 26 हजार पदों पर गत वर्ष भर्ती निकाली थी। जिसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा गत माह अजमेर में आयोजित की गई। दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता को कम हाइट होने का हवाला देते हुए बाहर कर दिया।

इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि दक्षता परीक्षा में उसकी हाइट को गलत तरीके से नापा गया है। ऐसे में मेडिकल बोर्ड के जरिए उसकी हाइट का पुन: परीक्षण कराया जाए। वहीं अदालत के सामने आया कि कम हाइट नापने के कई प्रकरण हाईकोर्ट आ चुके हैं। इस पर अदालत ने संबंधित उपकरण को हाईकोर्ट लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अदालत ने मौके पर ही हाइट का परीक्षण कर याचिका को खारिज कर दिया।

राजस्थान में 4 लाख 80 हजार जल संरक्षण एवं जल संचयन संरचनाओं का निर्माण हुआ : राठौड़

सांसद मदन राठौड़ ने भूजल सरंक्षण की दिशा में किए जा कार्यों को लेकर लगाए गए सवाल का जलशक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने दिया जवाब

जयपुर। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सहित देशभर में तेजी से भूजल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए राजस्थान में 4 लाख 80 हजार तो देशभर में 98 लाख जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन सरंचनाओं को निर्माण करवाया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश के 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित योजनाओं तक को शुरू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। राठौड़ द्वारा देशभर में तेजी से गिरते भूजल स्तर के विषय पर लगाए गए सवाल के जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने ये जानकारी दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 2019 से देशभर में जल शक्ति अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश भर में वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं तैयार करने जैसी विभिन्न गतिविधियों को चलाया जा रहा है। जल शक्ति अभियान 2024 के तहत राजस्थान के जल कमी वाले 10 जिलों सहित देशभर के 151 जिलों में विशेष रूप से जल सरंक्षण के लिए कार्य किए जा रहे है।

राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर प्लान 2020 को राजस्थान सहित देशभर के लिए लागू किया गया। इसमें देशभर में 185 बिलियन घन मीटर जल के लिए 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की ओर से राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और सीकर सहित राजस्थान के चयनित जल कमी वाले जिलों में बांध, चेक बांध, एनीकट और तालाबों का पुनर्भरण और निर्माण करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से मिशन अमृत सरोवर अभियान के तहत राजस्थान सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरूद्धार किया जा रहा है।

पेपर लीक मामले में आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियन्ता भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 के पेपर लीक मामले में वांछित चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वी के सिंह ने बताया कि फरार वांछित कमलेश कुमार मीणा निवासी गोविंदगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण को जयपुर के पानीपेच तिराहा जयपुर से गिरफ्तार किया गया।

स्वास्थ्य कार्मिकों एवं रोगियों से संवाद कर जांची स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

वीडियो कॉल से संवाद कर प्रमुख शासन सचिव ने बालोतरा जिले में की शुरूआत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निरंतर तकनीकी नवाचार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने अभिनव पहल करते हुए चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल के माध्यम से सीधा औचक संवाद प्रारंभ किया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इस नवाचार की शुरूआत बालोतरा जिले के जसोल क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मूंगड़ा में वीडियो कॉल कर की। उन्होंने अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक, बारां जिले के अटरू, चूरू जिले के सरदार शहर, डीग जिले के नगर एवं ब्यावर जिले के जैतारण ब्लॉक के चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। राठौड़ ने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संवाद कर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राठौड़ ने लाभार्थियों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता के संबंध में फीडबैक भी लिया। आएमएसएसीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक भारती दीक्षित, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका गोस्वामी, निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर, निदेशक आरसीएच डॉ. सुनीत सिंह राणावत सहित अन्य निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, परियोजना निदेशक, स्टेट नोडल ऑफिसर, संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित राज्य, संभाग एवं जिला स्तर के 100 से अधिक अधिकारियों ने दो घंटे में एक हजार से अधिक कॉल कर करीब 1 हजार चिकित्सा संस्थानों में सीधा संवाद किया।

विद्युत प्रसारण निगम में 94 अभियन्ताओं को पदोन्नति

जयपुर। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 94 सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को पदोन्नत कर खाली पदों पर पदस्थापित किया गया है।

जिन अभियन्ताओं को अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नत किया गया है, उनमें अमर दत्त व्यास, राजेन्द्र प्रसाद आर्य, जगदेव सिंह, मानसिंह, कृष्ण मीणा, रामावतार मीणा, जी.एस. मेघवाल, डेडा राम, एल. के. सालवी, डी.एस. नागर, चीमा राम चौधरी, सावर मल यादव, शिवराज चौधरी, अशोक कुमार शर्मा, दिलीप सैनी, दीपक कुमार शर्मा, सुनील कुमार यादव, सोहन लाल सैनी, मनोज कुमार सोनी, कुसुमलता चौहान, राजवीर सिंह, नरेश सैनी, राजेश कुमार, राजेश जैन, अशोक कुमार पाण्डे, आनन्द कुमार लामोरिया, अमर चन्द सैनी, एल. आर. सिरवी, संध्या चौहान, राजेश कुमार सवेता, महावीर सिंह, सुरेन्द्र कुमार, शैलेश सैनी, अभय कुन्तल, हरभजन सिंह, प्रेम प्रकाश, भारत भूषण शर्मा, अश्वनी कुमार, निर्मला गौड़, कृष्ण गोपाल, विजय बहादुर शामिल हैं।

केन्द्र ने जयपुर के लिए पर्यटन की दो योजनाएं स्वीकृत की

जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा भेजी गयी क़रीब 145 करोड़ की दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को इस संदर्भ में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने इन कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का भरोसा दिलाया था।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की थी और उसके बाद से ही वे जल महल और आमेर-नाहरगढ़ के विकास के लिए रोप-वे तथा अन्य योजनाओं की केन्द्र द्वारा स्वीकृति के लिए प्रयासरत थी।

दिया कुमारी ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल-इंजन की सरकार का पूरा लाभ राजस्थान को मिल रहा है। उन्होंने आशा जताई की केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे 145 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इन कार्यों के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जल महल और आमेर-नाहरगढ़ की विकास परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार करना, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों की सफलता है। पर्यटन में पूंजीगत व्यय के अलावा, नाहरगढ़-आमेर के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को रोप-वे योजनाओं के लिए भी प्रस्ताव भिजवाये गये है, जिनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए दिया कुमारी ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है वही जलमहल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग तथा राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ेगा

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का सुदृढीकरण करने के साथ ही इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। उपचार हेतु औषधियो का दायरा बढाने के उद्देश्य से तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को प्रबंध निदेशक आरएमएससीएल नेहा गिरि की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में आवश्यक दवा सूची में नवीन औषधियों को शामिल करने, पूर्व से उपलब्ध औषधियों की श्रेणी परिवर्तन किये जाने से संबंधित निर्णय लिये लिए गए। बैठक में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल करने पर विचार किया गया। बैठक में उपस्थित चिकित्सा एवं फार्मा विशेषज्ञों ने दवाओं की उपलब्धता, आवश्यकता, आपूर्ति आदि के बारे में सुझाव दिए। गिरि ने बताया कि बैठक में 390 औषधियों का परीक्षण कर किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में हुए निर्णयों के अनुरूप जल्द ही नवीन दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जाएगा। इससे रोगियों को निकट के चिकित्सा संस्थान पर अधिक से अधिक औषधियां उपलब्ध हो सकेंगी।

एस.एम.एस. अस्पताल प्रशासन ने एक करोड़ रु. की पार्किंग बिना किसी टैंडर चहेते ठेकेदार को सौंपी!

सवाई मानसिंह अस्पताल के मुख्य भवन और धनवंतरी ओ.पी.डी. की भूमिगत पार्किंग में कच्ची पर्चियों की आड़ में दुगुना पार्किंग शुल्क वसूल रहा ठेकेदार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल की भूमिगत पार्किंग का ठेका जे.बी.एम. कंपनी से वापस लेकर चहेती फर्म को सौंपने का बड़ा मामला सामने आया है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ रु. का राजस्व देने वाली इस पार्किंग को अस्पताल प्रशासन ने बिना किसी टैंडर चहेती फर्म मैसर्स ऋतुराज एसोसिएट्स के संचालक बृजराज सिंह को सौंप दिया। यह ठेकेदार सवाई मानसिंह अस्पताल के नाम की कच्ची पर्चियों की आड़ में आमजन से दुगुना पार्किंग शुल्क वसूल रहा है। पूरा प्रकरण उजागर होने के बावजूद चिकित्सा विभाग के अफसरों की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सवाई मानसिंह अस्पताल के मुख्य भवन और धनवंतरी ओ.पी.डी. की भूमिगत पार्किंग में इन दिनों दुपहिया वाहन चालकों से 20 रु. और चौपहिया वाहनों से 40 रु. का पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। जबकि पूर्व में यहां जिस जे.बी.एम. कंपनी के पास ठेका था, वह क्रमश: 10 रु. और 20 रु. शुरूआती 10 घंटे के लिए वसूलती थी।

सूत्रों की मानें तो सवाई मानसिंह अस्पताल के मुख्य भवन और धनवंतरी ओ.पी.डी. की भूमिगत पार्किंग का संचालन इन दिनों मैसर्स ऋतुराज एसोसिएट्स फर्म के संचालक बृजराज सिंह द्वारा किया जा रहा है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि, एस.एम.एस. अस्पताल की पार्किंग के टैंडर प्रक्रिया पर अदालत ने स्टे दे रखा है। गत 2 वर्षों से इस भूमिगत पार्किंग का संचालन जे.बी.जे. कंपनी कर रही थी। परंतु गत 21 नंवबर को सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने इस कंपनी को पत्र लिखकर यह कहते हुए ठेका निरस्त कर दिया कि, अब इस पार्किंग को एस.एम.एस. अस्पताल प्रशासन के स्तर पर संचालित किया जायेगा। अधीक्षक सुशील भाटी के इस पत्र के बाद 22 नवंबर को जे.बी.जे. कंपनी ने पार्किंग का जिम्मा अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया।

पार्किंग ठेकेदार बृजराज सिंह

पर्चियों पर अंकित 40 रु. शुल्क

- **पूर्व में अस्पताल की पार्किंग में जे.बी.एम. कंपनी द्वारा दुपहिया वाहनों से 10 रु. तथा चौपहिया वाहनों से 20 रु. शुल्क शुरूआती 10 घंटे के लिए लिया जाता था, अब नया ठेकेदार यह क्रमशः 20 और 40 रु. के हिसाब से राशि वसूल रहा है।**
- **बड़ा सवाल यह है कि, जब एस.एम.एस. अस्पताल की पार्किंग की टैंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का स्टे है तो फिर आखिर चिकित्सा अधीक्षक ने आनन-फानन में जे.बी.एम. कंपनी से पार्किंग वापस लेकर बिना किसी टैंडर चहेते मैसर्स ऋतुराज एसोसिएट्स फर्म के संचालक बृजराज सिंह को क्यों सौंपा**
- **बताया जा रहा है कि सवाई मानसिंह अस्पताल व धनवंतरी ओ.पी.डी. की भूमिगत पार्किंग के ठेके से हॉस्पिटल प्रशासन को सालाना करीब 1 करोड़ रु. का राजस्व मिलता था, लेकिन अब यह राशि प्राइवेट ठेकेदार की जेब में जा रही है।**

मजेदार बात यह है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने जे.बी.जे. कंपनी से यह पार्किंग लेते ही इसका संचालन अगले ही दिन प्राइवेट लोगों को सौंप दिया, अब यहां पर 10 व 20 रु. के शुल्क के बजाय 20 व 40 रु. की राशि वसूली जा रही है। ठेकेदार द्वारा लिए गए दुगुने शुल्क की कुछ पर्चियां गत 23 नवंबर को भी सामने आई थी। ऐसे ही पर्चियां 28 नवंबर को भी सामने आयी है, जिसमें चौपहिया वाहनों से 40 रु. का शुल्क लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पार्किंग शुल्क की "अवैध वसूली" का यह पूरा खेल सवाई मानसिंह अस्पताल के नाम पर कच्ची पर्चियों पर खेला जा रहा है।

जबकि सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनकी परिजनों के लिए वाहन पार्किंग शुल्क दुपहिया वाहनों के लिए 10 और चौपहिया वाहनों के लिए 20 रुपये शुरूआती 10 घंटों के लिए तय कर रखे हैं।

पिछले दिनों जब इस प्रकरण में एस.एम.एस. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सुशील भाटी से बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि, पार्किंग का संचालन अस्पताल स्वयं कर रहा है, कुछ निजी लोगों को पार्किंग की व्यवस्था के लिए "हायर" किया है। परंतु 28 नवंबर को कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें अस्पताल की भूमिगत पार्किंग का संचालन अन्य ठेकेदार बृजराज सिंह द्वारा करना सामने आया।

बृजराज सिंह की फर्म ऋतुराज एसोसिएट्स पूर्व में भी सवाई मानसिंह अस्पताल की धनवंतरी ओ.पी.डी. की भूमिगत पार्किंग का संचालन कर चुकी है। यहां तक कि उनके द्वारा नगर निगम के सरकारी पार्किंगस्थल रामलीला मैदान का ठेका भी लिया गया था। ऐसे में सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठ रहा है कि, क्या उन्होंने दूसरे ठेकेदार को सालाना 1 करोड़ का राजस्व देने वाली पार्किंग का ठेका बिना किसी टैंडर सौंप दिया है।

हालात ऐसे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने ना तो कम्प्यूटर जनित पर्चियों के लिए पॉस मशीनें दे रही है और ना ही निर्धारित शुल्क राशि के कोई बोर्ड पार्किंग स्थल पर लगा रखे हैं। इस वजह से आमजन को मजबूरन दुगुना शुल्क चुकाना पड़ रहा है।

सूत्रों की मानें तो सवाई मानसिंह अस्पताल की दोनों पार्किंग में प्रतिदिन करीब 500 चौपहिया और 1500 दुपहिया वाहन पार्क किए जाते हैं। इसमें से 300 चौपहिया और 500 दुपहिया वाहन अस्पताल प्रशासन के लिए नि:शुल्क पार्किंग शामिल है। शेष वाहन मालिकों से प्रतिदिन करीब 50 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है।

सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन ने "प्राइवेट लोगों" को पार्किंग का संचालन तो सौंप दिया, लेकिन वह कितनी राशि अस्पताल प्रशासन को जमा करवाएंगे, यह तय नहीं किया है। जबकि इससे पहले जे.बी.जे. कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ रु. अस्पताल प्रशासन को जमा करवाये जाते थे।

तीन वर्ष पूर्व यह दोनों ठेके 75 लाख रु. में इस कंपनी को दिए गए थे, सालाना 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़कर 1 करोड़ रु. पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि शुरूआती 10 घंटे के लिए एसएमएस अस्पताल की इस पार्किंग में साईकिल के लिए पांच रु., बाइक-स्कूटर के लिए 10 रु. और चौपहिया वाहन के 20 रुपये तय है। इसके अलावा 24 घंटे के लिए साईकिल के लिए 10, बाइक-स्कूटर के लिए 20 और चौपहिया वाहन के लिए 40 रुपये तय है।

ऐसी छवि बनाएं कि लोग याद करते रहें : देवनानी

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुरेश चन्द्र पारीक और जितेन्द्र सारवान को सेवानिवृत्त होने पर माला व साफा पहनाकर व शॉल ओढाकर स्मृति चिन्ह भेंट किये।

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि अपने कर्म, व्यवहार, पहल, निष्ठा और ईमानदारी से ऐसी छवि बनाएं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी लोग याद करते रहें।

देवनानी ने यह बात गुरूवार को यहां विधान सभा में सहायक सचिव सुरेश चन्द्र पारीक और जितेन्द्र सारवान के सेवानिवृत्ति पर आयोजित समारोह में कही। देवनानी ने दोनों अधिकारियों को माला व साफा पहनाकर व शॉल ओढाकर स्मृति चिन्ह भेंट किये। देवनानी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को तनाव नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिल सकता है। लम्बी अवधि की राज्य सेवा की स्मृतियों को स्मरण करने का यह दिवस यादगार होता है। साथी कर्मियों और परिवारजन को मिलकर इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। देवनानी ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद मानव सेवा का स्टार्टअप आरम्भ करें। जीवनभर सक्रिय बने रहने का प्रयास करें। अपने परिवारजन को विधानसभा, राजनैतिक आख्यान संग्रहालय और संविधान दीर्घा अवश्य दिखाएं। परिवारजन को भी यह महसूस होना चाहिए कि उनके परिवार का सदस्य राजस्थान विधानसभा जैसे गरिमामय स्थल पर काम कर रहा है। उनके लिए भी यह गौरव की बात होगी। इस अवसर पर विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के. के. शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, उप सचिव संजीव शर्मा, वित्तीय सलाहकार अपूर्व जोशी, अधिकारी संघ के अध्यक्ष लोकेश जैन और विधान सभा सहकारी साख समिति के अध्यक्ष रवि जैन सहित अन्य पदाधिकारी तथा विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

कुण्डली, हस्तरेखा और कर्म की त्रिवेणी का संगम बने ज्योतिषि : देवनानी

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि ज्योतिष विद्या भारत में ही उत्पन्न हुई और यहीं से सम्पूर्ण विश्व में इस विद्या का प्रचार- प्रसार हुआ है। यह विद्या अपने आप में शुद्ध गणित है। इसके अध्ययन के लिए अन्य देश के लोग भारतीय विद्वानों से सम्पर्क करते हैं। यह भारत के लिए गौरव है। देवनानी ने ज्योतिषियों का आव्हान किया है कि वे भारतीय सनातन संस्कृति के वाहक बने।

देवनानी गुरुवार को यहां नारायण सिंह सर्किल स्थित इन्द्रलोक सभागार में सर्वशक्तिमान अन्तरराष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। देवनानी ने स्वस्ति वाचन के गुंजायमान के साथ दीप प्रज्जवलित कर सम्मेलन का शुभारम्भ किया। देवनानी ने गृह नक्षत्रों की चाल से सटिक भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषों को वंदन करते हुए कहा कि भारत में विकसित हुई गृह नक्षत्रों की गणना पद्धति से ब्राह्माण्ड की रीति-नीति के साथ पंचांग की रचना विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। भारत के शून्य के अविष्कारक आर्यभट्ट जैसे विद्वान के द्वारा आर्यभट्टीयम के माध्यम से गणना सिखाई तो प्रख्यात खगोलविद वराहमिहिर ने अपनी कृति सिद्धान्तपंचिका के माध्यम से कालगणना की विधि लोगों को सिखाई थी। इनके अलावा ब्रह्मगुप्त की कृति "ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त", अल्स का "शिष्यधीवृद्धि", श्रीपति का "सिद्धान्तशेखर", भास्कराचार्य का "सिद्धान्तशिरोमणि", गणेश का "ग्रहलाघव" तथा कमलाकर भट्ट का "सिद्धान्त-तत्व-विवेक" भारतीय ज्योतिष व गणित की असाधरण कृति हैं।